



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 107]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

प्रकरण सं. OI-22/2017

विषय : चीन जन. गण., बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरु के मूल के अथवा से निर्यातित 'एक्रिलिक फाइबर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।

फा. सं. 14/50/2016-डीजीएडी.—यतः, मै. इंडियन एक्रिलिक्स लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. (जिन्हें आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरु (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित 'एक्रिलिक फाइबर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए संयुक्त रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार का एक्रिलिक फाइबर है (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है)। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पालिमेर की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल इकाइयों (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भार के

अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत होता है। एक्रिलिक फाइबर शब्दों में एक्रिलिक स्टेपल, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टाप शामिल हैं। दूसरे शब्दों में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टाप को सामान्य शब्दावली में एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।

4. एक्रिलिक फाइबर एक्रिलिक स्टेपलफाइबर, एक्रिलिक टो अया एक्रिलिक टाप हो सकता है। एक्रिलिक स्टेपल फाइबर और एक्रिलिक टो के बीच केवल लंबाई का अंतर है। यदि 2 मीटर से अधिक लंबाई होती है तो उसे टो के रूप में जाना जाता है और कट लंबाई में मामले में इसे स्टेपल फाइबर के रूप में जाना जाता है। एक्रिलिक फाइबर के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं।

5. एक्रिलिक फाइबर लाइटवेट, मुलायम, और गर्म, ऊन जैसे स्पर्श वाला होता है। इसके फाइबर काफी लोचशील होते हैं और अन्य सिंथेटिक तथा प्राकृतिक रेशों की तुलना में अम्लों और अलकलीज से अधिक प्रतिरोध दर्शाते हैं। एक्रिलिक फाइबर ऊन का एक किफायती स्थापन्न है।

6. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अधीन उपशीर्ष 5501.5503 और चार-अंकीय स्तर पर 5506 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। यह उत्पाद एचएस कोड 550130, 550330 और 550630 के अधीन शामिल है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन संयुक्त रूप से मै. इंडियन एक्रिलिक्स लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. द्वारा दायर किया गया है। एक अन्य उत्पादक अर्थात् मै. वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड है। इस कंपनी ने यूरोप से संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का आयात किया है। एक आवेदक कंपनी ने गैर-संबद्ध देश अर्थात् थाइलैंड से अग्रिम लाइसेंस के अधीन संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आवेदक ने यह घोषणा की है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक से न तो संबंधित हैं और न ही संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

घ. शामिल देश और निर्धारित न्यूनतम सीमा

9. यह आवेदन चीन जनवादी गणराज्य, बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू से एक्रिलिक फाइबर के पाटन के संबंध में दायर किया गया है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयातों की मात्रा विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है। संबद्ध देशों के अलावा, थाइलैंड से भी आयात हो रहे हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। वर्तमान जाँच केवल चीन जनवादी गणराज्य, बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के संबंध में है।

च. सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में, संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान उत्पादन लागत के आधार पर संबद्ध देशों में कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं की प्रचलित कीमतों, सबसे कुशल घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों जमा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करके लगाया गया है।

छ. निर्यात कीमत

11. निर्यात कीमत का निर्धारण आवेदक द्वारा प्रस्तावित जाँच अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आकड़ों के आधार पर किया गया है। निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े, कमीशन, और बैंक प्रभारों तथा वैट समायोजनों, जहां लागू हों, के लिए आवश्यक समायोजनों के पश्चात निर्धारित किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है जैसा कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों द्वारा साक्ष्यांकित है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना से पता चलता है कि देश में मांग में वृद्धि और देश में क्षमता की उपलब्धता के बावजूद जॉच अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और उससे बाजार में कम कीमत पर बिक्री हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट आई है। यह गिरावट जॉच अवधि के दौरान और अधिक है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ रही है।

ञ. जॉच की शुरुआत

14. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जॉच की शुरुआत करते हैं।

ट. जांच अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जॉच के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तावित जॉच अवधि 1 जुलाई, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने) की ली है। क्षति जॉच अवधि में 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें जिससे प्राधिकारी समयबद्ध ढंग से समुचित निर्धारण कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग, जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

dgad.india@gov.in

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

ड. समय-सीमा

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के चालीस (40) दिनों के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर और तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना अनिवार्य रूप से मूल प्रतियों और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. यह नोट किया जाए कि यदि किसी हितबद्ध पक्ष से निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय आधार पर प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को किए गए अनुरोधों को अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा जिसे अन्य हितबद्ध पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी मूल प्रति के साथ दो-दो (2) प्रतियों में दोनों अंशों की साफ्ट प्रतियां भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

21. दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

22. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना हो सकती है जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता व्यापार संवेदी सूचना होने का दावा करता है जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना के प्रदाता का वाणिज्यिक हित प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे। स्वाभाविक रूप से गोपनीय और गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

त. असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2017

Case No. OI- 22/2017

Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of "Acrylic Fibre" originating in or exported from People's Republic of China, Belarus, Ukraine, European Union and Peru.

No. 14/50/2016-DGAD.—Whereas, M/s. Indian Acrylics Limited and M/s. Pasupati Acrylon Ltd (hereinafter referred to as the applicant) jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as the Act) and Customs

Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the Rules) as amended from time to time, for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of “Acrylic Fibre” originating in or exported from People’s Republic of China, Belarus, Ukraine, European Union and Peru (also referred to as the Subject Countries).

2. And whereas, the Authority finding sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and ‘injury’ exists justifying initiation of an anti-dumping investigation, hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to consider recommending an amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

A. Product under consideration and Like Articles

3. The product under consideration in the present application is Acrylic Fibre of all types (hereinafter referred as subject goods). Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The terms acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.
4. Acrylic Fibre can be acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. The only difference between acrylic staple fibre and acrylic tow is the difference in length. In case of length more than 2 Meters, it is known as tow and in case of cut lengths, it is known as staple fibre. All forms of acrylic fibre are within the scope of the product under consideration.
5. Acrylic fibre is lightweight, soft, and warm, with a wool-like feel. Its fibers are very resilient and shows high resistance to acids and alkalies compared to both other synthetics and natural fibers. Acrylic Fibre is an economical substitute of wool.
6. Subject goods are classified under chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 5501, 5503 and 5506 at 4-digit level. The product is covered under HS code 550130, 550330 and 550630. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

B. Domestic Industry & Standing

7. The application has been jointly filed by M/s. Indian Acrylics Limited and M/s. Pasupati Acrylon Ltd. There is one more producer namely M/s. Vardhman Acrylics Limited. The company has imported significant volumes of subject goods from Europe. One of the applicant company has imported insignificant quantity of the subject goods from non-subject countries i.e. Thailand under advance license. Applicants have declared that they are neither related to producer of subject goods in the subject countries nor to an importer of subject goods from subject countries. The Authority holds that the applicant companies constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

C. Like Article

8. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the domestic industry in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Countries involved and de minimis limits

9. The application has been filed in respect of the dumping of Acrylic Fibre from People’s Republic of China, Belarus, Ukraine, European Union and Peru. The imports from each of the subject countries are above de minimis limits. Apart from the subject countries imports are also taking place from Thailand which is attracting Anti-Dumping Duty. The present investigation is with respect to only People’s Republic of China, Belarus, Ukraine, European Union and Peru (hereinafter referred to as subject countries).

E. Normal value

10. The applicant has claimed that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries, the normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production, taking into account prevailing prices of raw materials and utilities in

subject countries, conversion costs of the most efficient domestic industry, and duly adjusted selling, general & administration expenses, plus a reasonable profit.

F. Export price

11. The export price has been determined on the basis of import data obtained from DGCI&S for the period of investigation proposed by the applicants. The net ex-factory export prices have been determined after due adjustments towards ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, commission and bank charges, and VAT adjustments, wherever applicable.

G. Dumping margin

12. The normal value has been compared with export price at ex-factory level. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is higher than the ex-export price, showing that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters of the subject countries. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

H. Evidence of Injury and Causal Link

13. The applicant has claimed that they have suffered material injury as evidenced by volume and price impact of the dumped imports from the subject countries. Information provided by the applicants shows that there has been significant increase in the volume of dumped imports during the period under examination despite moderation of demand in the country and availability of capacity in the country. The imports are *prima facie* undercutting the domestic prices and the same has led to price depression in the market. The production, capacity utilization, profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has declined. The decline is more pronounced within the investigation period. Therefore, *prima facie* it appears that the applicant domestic industry is suffering material injury as a result of dumped imports.

I. Initiation of the Investigation

14. The Authority finds sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

J. Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation proposed by the applicants is 1st July 2016 to 31st December 2016, However, the Authority has taken the period of investigation as 1st April 2016 to 31st March 2017 (12 Months). The injury investigation period shall cover the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation.

K. Submission of Information

16. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the known importers and users in India, and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address, so as to enable the Authority make appropriate determinations in a timely manner:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties

Department of Commerce, Jeevan Tara Building, 4th Floor, Parliament Street, New Delhi -110001

dgad.india@gov.in

17. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the Authority at (**www.dgtr.gov.in**) within the time limit set out below.

L. Time Limit

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 2 weeks from the date of this notification and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

19. It may be noted that if no information is received from an interested party within the prescribed time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record, in accordance with the Rules.

M. Submission of information on confidential basis

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority, including questionnaire response on confidential basis, are required to file a non-confidential version of the submissions made, which will be made available to all other interested parties to make their comments. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
21. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked so at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
22. The confidential version may contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as business proprietary information, disclosure of which will adversely affect the commercial interest of the supplier of such information. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out. In case indexation is not feasible, the information may be summarized, depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reason why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either not willing to make the information public, or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

25. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by all interested parties to the investigation.

O. Non-cooperation

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available with it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority